वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के निजी क्षेत्र सहयोग मंच पर संबोधन, 26 मार्च, 2025, मुंबई*

श्री संजय मल्होत्रा

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के निजी क्षेत्र सहयोग मंच (पीएससीएफ) 2025 में शामिल होना मेरे लिए खुशी की बात है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि यह पहली बार है जब यह फोरम भारत में आयोजित किया जा रहा है। हमें यह अवसर देने के लिए मैं एफएटीएफ का आभार व्यक्त करता हूँ। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में सचिव के रूप में अपनी पिछली भूमिका में, मुझे पिछले वर्ष हमारे पारस्परिक मूल्यांकन के दौरान एफएटीएफ के साथ निकटता से जुड़े रहने का अवसर मिला था।

एफएटीएफ

एफएटीएफ जो अवैध वित्तपोषण से निपटने के लिए मानक निर्धारण निकाय है, 1989 में अपनी स्थापना के बाद से एक लंबा सफर तय कर चुका है। पिछले कुछ वर्षों में, यह केवल 16 सदस्यों वाले संगठन से 40 सदस्यों वाले वैश्विक मंच में विकसित हुआ है। एफएटीएफ-शैली के क्षेत्रीय निकायों के माध्यम से[1], इसकी पहुंच और भी व्यापक हुई है। एफएटीएफ द्वारा विकसित मानकों का उपयोग 200 से अधिक न्यायालयों द्वारा, धन शोधन [मनी लॉन्ड्रिंग (एमएल)], आतंकवाद का वित्तपोषण (टीएफ) और 'प्रसार वित्तपोषण' का प्रतिरोध करने के लिए किया जाता है। इन मानकों के कार्यान्वयन ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने और दुनिया को एक सुरक्षित स्थान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

एफएटीएफ द्वारा भारत का पारस्परिक मूल्यांकन

भारत, धन शोधन निवारण [एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल)] और आतंकवाद वित्तपोषण का प्रतिरोध करने (सीएफटी) को बहुत महत्व देता है। पिछले साल, एफएटीएफ द्वारा भारत का पारस्परिक मूल्यांकन किया गया था। भारत को ‹नियमित अनुवर्ती› श्रेणी में रखा गया था, यह एक ऐसा सम्मान है जो केवल कुछ अन्य जी20 देशों को ही प्राप्त है[2]। यह हमारे प्रभावी एएमएल और सीएफटी ढांचे की स्वीकृति है। यह एएमएल और सीएफटी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह हमारे देश में वित्तीय प्रणाली के निर्माण और निरंतर सुधार एवं मजबूती के कई वर्षों का परिणाम है।

यह भारत सरकार के नेतृत्व में सभी हितधारकों के सहयोगात्मक प्रयासों के कारण संभव हुआ, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं और नामित गैर-वित्तीय व्यवसाय और पेशे, विनियामक और राज्य सरकारें शामिल हैं। वित्तीय प्रणालियों को सुरक्षित रखने में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समुचित सावधानी प्रक्रियाओं को लागू करने, मजबूत जोखिम आकलन करने, लेन-देन की निगरानी करने और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने में उनकी भूमिका वित्तीय प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। वे संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करते हैं और अवैध वित्त तंत्र (नेटवर्क) को नष्ट करने में सरकारी एजेंसियों की मदद करते हैं।

मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी वित्तीय प्रणाली की अखंडता की सुरक्षा के लिए आधार बनाती है। भारत में, हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हितधारकों के बीच घनिष्ठ सहयोग के महत्व को पहचानते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत में वित्तीय प्रणाली के एक बड़े हिस्से के नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में, एफएटीएफ की सिफारिशों के अनुरूप, वित्तीय प्रणाली के इस हिस्से में एक मजबूत एएमएल और सीएफटी ढांचे के कार्यान्वयन के निर्माण और सुनिश्चित करने की दिशा में लगन और लगातार काम कर रहा है। रिज़र्व बैंक ने विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। इसी तरह, वित्तीय आसूचना इकाई (एफआईयू)-भारत ने भी घनिष्ठ संपर्क और सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए सार्वजनिक-निजी सहयोग मंच – एफपीएसी[3] की स्थापना

* वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के निजी क्षेत्र सहयोगी फोरम में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा का संबोधन, 26 मार्च 2025, मुंबई।

[1] अपने 40 सदस्यों के अतिरिक्त, एफएटीएफ को नौ एफएटीएफ-शैली क्षेत्रीय निकायों (एफएसआरबी) का भी समर्थन प्राप्त है।

[2] https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2056773

[3] एएमएल/सीएफटी (एफपीएसी) में भागीदारी के लिए एफआईयू-भारत पहल, एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) ढांचा, जनवरी 2022 में शुरू किया गया था, ताकि एएमएल/सीएफटी डोमेन में एफआईयू-भारत और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाया जा सके।

की है। इसने एआरआईएफसी[4] की स्थापना का भी समर्थन किया है जो निजी क्षेत्र की रिपोर्टिंग संस्थाओं के बीच सहयोग करने के लिए एक अंतर-क्षेत्रीय (क्रॉस सेक्टोरल) फोरम है।

इन सहयोगात्मक प्रयासों का ही नतीजा है कि हम एक मजबूत और सुदृढ़ एएमएल और सीएफटी ढांचा बनाने और प्रदर्शित करने में सक्षम हुए हैं। मैं सभी हितधारकों, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र में विनियमित संस्थाओं के साथ-साथ नामित गैर-वित्तीय व्यवसायों और व्यवसायों को सफल पारस्परिक मूल्यांकन के लिए बधाई देता हूं।

हालाँकि, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय और वैश्विक वित्तीय प्रणालियों के लिए धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण से खतरे लगातार बढ़ रहे हैं और अधिक जटिल होते जा रहे हैं। यह मुख्य रूप से तकनीकी प्रगति के कारण है। इन खतरों का प्रभावी ढंग से प्रतिरोध करने के लिए हमें विभिन्न हितधारकों - सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में वित्तीय संस्थाओं, नागरिक समाज और अन्य के बीच घनिष्ठ सहयोग जारी रखने की आवश्यकता है।

आपसी मूल्यांकन प्रक्रिया कठोर और विस्तृत थी। इसने हमें अपनी ताकत के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हुए, हमारे एएमएल-सीएफटी ढांचे में सुधार के कुछ क्षेत्रों पर प्रकाश डाला है। हम इस मूल्यांकन की संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने और उनका प्रतिरोध करने हेतु अपनी वित्तीय प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए दृढ़ हैं। हम इस दिशा में निरंतर सुधार के लिए प्रयास जारी रखेंगे।

पीएससीएफ 2025 की कार्यसूची (एजेंडा) से संबंधित कुछ विचार

मुझे बताया गया है कि कल के सत्र बहुत ही रोचक थे और उनमें जीवंत चर्चा हुई। आज और कल की कार्यसूची को देखते हुए, मुझे विश्वास है कि समकालीन विषयों, जैसे - एएमएल-सीएफटी परिदृश्य, वित्तीय समावेशन और मानव चैनल, पर्यवेक्षण के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण, डिजिटलीकरण और सूचना साझाकरण, लाभकारी स्वामित्व और 'प्रसार वित्तपोषण' (घातक हथियारों के विकास और प्रसार को वित्तपोषण) का प्रतिरोध करना, जैसे विषयों पर विचार-विमर्श भी रोमांचक होगा। मैं इन क्षेत्रों पर फोरम के लिए अपने कुछ विचारों को रेखांकित करना चाहता हूँ।

सबसे पहले, जबकि हम सभी अपने वित्तीय सिस्टम को धन शोधन और आतंकी वित्तपोषण के खिलाफ़ सुरक्षित और संरक्षित बनाना जारी रखते हैं, हमें नीति निर्माताओं के रूप में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे उपाय अति उत्साही न हों और वैध गतिविधियों और निवेशों को बाधित न करें। आप इस बात की सराहना करेंगे कि कई कानून और नियम, जिनमें से प्रत्येक की अपनी-अपनी बारीकियाँ हैं, विनियमित वित्तीय सेवा प्रदाताओं पर अनुपालन का उच्च स्तर का बोझ डालते हैं। यह एएमएल-सीएफटी के संदर्भ में भी प्रासंगिक है। इसलिए, हमें ऐसे कानून और नियम बनाने की ज़रूरत है जो सर्जिकल सटीकता के साथ केवल गैर-कानूनी और अवैध को लक्षित करें, बजाय इसके कि उन्हें कुंद औजारों के रूप में इस्तेमाल किया जाए जो अनजाने में ईमानदार लोगों को भी चोट पहुँचाते हैं।

इसी तरह, कानूनी ढांचे और विनियमों को लागू करते समय भी, हमें व्यक्तियों और व्यवसायों पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखना होगा। इस संबंध में जोखिम-आधारित दृष्टिकोण की अनुशंसा की जाती है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह अनुपालन बोझ को कम करने की दिशा में एक कदम आगे है। हमें यह समझना चाहिए कि यह अंतिम समाधान नहीं है, क्योंकि कोई भी जोखिम-आधारित दृष्टिकोण परिपूर्ण नहीं होता; इसमें गलत सकारात्मक और गलत नकारात्मक परिणाम होंगे। हमें अपने जोखिम मूल्यांकन मॉडल को मजबूत बनाने के लिए इसे निरंतर परिष्कृत और बेहतर बनाते रहने की आवश्यकता है।

इन सुधारों को करने के लिए, हमें अपने डेटा की गुणवत्ता में सुधार करने और उभरती हुई तकनीकों का उपयोग करने की आवश्यकता है। इससे लेन-देन की स्क्रीनिंग और संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने में मदद मिलेगी, जिससे गलत सकारात्मक और गलत नकारात्मक कम होंगे। ग्राहक व्यवहार में बदलाव और उत्पादों और सेवाओं के विकास के परिणामस्वरूप धन शोधन के क्षेत्र में विकसित परिदृश्य को देखते हुए, हमें एएमएल जोखिम मूल्यांकन ढांचे को लगातार बढ़ाने और एमएल और अन्य जोखिमों के प्रभाव का आकलन करने के बाद नियमित

[4] एएमएल/सीएफटी के लिए भारत में रिपोर्टिंग संस्थाओं का गठबंधन (एआरआईएफसी) भारत में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित रिपोर्टिंग संस्थाओं के बीच एक निजी-निजी भागीदारी पहल है, जिसका उद्देश्य सूचना साझाकरण, ज्ञान उत्पादों का विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रमाणन को सुविधाजनक बनाना है।

आधार पर उचित प्रणाली संवर्द्धन करने की आवश्यकता है। वित्तीय दुनिया में नवीनतम रुझानों और घटनाक्रमों को समझने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जिसका अपराधियों द्वारा इसतेमाल किया जा सकता है और तदनुसार ऐसे उपकरण और सक्षम ढांचे विकसित किए जाने चाहिए जो हमें संदिग्ध लेनदेन और गतिविधियों का जल्द पता लगाने और अग्रसक्रिय कार्रवाई करने की अनुमति दें। नए तकनीकी उपकरणों और मॉडलों को अपनाने के साथ, मुझे यकीन है कि एएमएल-सीएफटी जोखिम आकलन को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। मैं, आप सभी से एएमएल-सीएफटी जोखिमों की पहचान, शमन और पर्यवेक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा करने और उन्हें साझा करने का आग्रह करूंगा। इससे न केवल विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन का बोझ कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि पर्यवेक्षी संसाधनों का इष्टतम आबंटन भी होगा।

जबकि भारत ने वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम इसे व्यापक और गहन बनाते रहें। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एफएटीएफ मानकों पर चर्चाओं में वित्तीय समावेशन और वित्तीय एकीकरण को संरेखित करने में आने वाली चुनौती का समाधान खोजने की आवश्यकता है, विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विनियमन वित्तीय समावेशन में अनपेक्षित अवरोध पैदा न करें। हमें समुचित सावधानी बाध्यताओं को पूरा करते समय ग्राहक अधिकारों और सुविधा के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि मैक्सिकन प्रेसीडेंसी के तहत अनुशंसा 1 और उसकी व्याख्यात्मक टिप्पणी में संशोधन वित्तीय अखंडता से समझौता किए बिना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का इरादा रखते हैं। मानवी सहायता का समर्थन करने वाले वित्तीय चैनलों की पहुँच बढ़ाने के लिए भी इसी तरह के दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

हाल के वर्षों में, डिजिटलीकरण का उपयोग ग्राहक ऑनबोर्डिंग और ग्राहक समुचित सावधानी (सीडीडी) प्रक्रियाओं में तेजी से किया जा रहा है। भारत ने इस संबंध में भी बड़ी प्रगति की है। डिजिटल केवाईसी और वीडियो केवाईसी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। एक अरब से अधिक व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखने वाली सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) इसका एक और उदाहरण है, जिसमें न केवल ग्राहकों के लिए बल्कि विनियमित संस्थाओं के लिए भी ग्राहक पहचान और समुचित सावधानी पूरी करने को आसान और निर्बाध बनाकर ग्राहक ऑनबोर्डिंग के एक नए युग की शुरुआत करने की क्षमता है। मुझे बताया गया है कि ग्राहक समुचित सावधानी के क्षेत्र में तकनीकी समाधानों की स्थिति पर विचार-विमर्श करने के लिए एक अलग सत्र है। ये चर्चा सीकेवाईसीआर की क्षमता और उपयोगिता को कई गुना बढ़ाने में सहायक हो सकती हैं।

इसके अलावा, सीडीडी की प्रक्रिया के दौरान, रिपोर्टिंग संस्थाएँ ग्राहकों से बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र करती हैं। इसके अलावा, वित्तीय आसूचना इकाइयों, विधि प्रवर्तन एजेंसियों और डेटा रजिस्ट्री के साथ जानकारी साझा करने की आवश्यकताएँ हैं, जिससे डेटा सुरक्षा और सहमति के बिना जानकारी साझा करने के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं। भारत ने हाल ही में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया है। विभिन्न न्यायालयों के अनुभवों के आदान-प्रदान से हमें अपने देश में कानून को बेहतर ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी।

एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र जिस पर चर्चा की आवश्यकता है, वह है ‘यात्रा नियम’। आज की दुनिया में, तेज भुगतान प्रणालियाँ वित्तीय पहुँच में क्रांति ला रही हैं और वित्तीय समावेशन को गहन बना रही हैं। भारत जैसे विकासशील देशों ने डिजिटल भुगतान को सुलभ, किफ़ायती और सुविधाजनक बनाने में बहुत प्रगति की है। जहाँ कार्ड नेटवर्क ने विकसित अर्थव्यवस्थाओं को भुगतान प्रणालियों को बेहतर बनाने में मदद की है, वहीं तेज़ भुगतान प्रणालियों ने उभरते बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद की है। हमने कुछ देशों के साथ तेज़ भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके सीमा पार भुगतान को भी सक्षम बनाया है। हम 2027 तक समावेशी सीमापार भुगतान की दिशा में जी20 रोडमैप के अगले चरण के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में काम करना जारी रखेंगे। इस संदर्भ में, एफएटीएफ अनुशंसा 16 (आर.16), जिसे ‘यात्रा नियम’ के रूप में जाना जाता है, पर चल रही चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। सीमापार भुगतान को तेज़, सस्ता, अधिक पारदर्शी और अधिक समावेशी बनाने के जी20 उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उनकी सुरक्षा और सुरक्षा को बनाए रखते हुए, ‘यात्रा नियम’ को प्रौद्योगिकी-तटस्थ बनाना वांछनीय होगा।

अंत में, 'प्रसार वित्तपोषण' से लड़ना और 'प्रतिबंधों से बचने की प्रवृत्ति' से निपटना विषयों की चर्चा में उन उत्पादों और सेवाओं जिनका सर्वाधिक दुरुपयोग होता है की पहचान से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने और ऐसे उत्पादों से संबंधित जोखिमों को कम करने की आवश्यकता है। यह फोरम इस संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ-साथ चुनौतियों पर भी चर्चा कर सकता है।

निष्कर्ष

अंत में, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि अपने सहयोगी प्रयासों के माध्यम से, हम वैश्विक वित्तीय ढांचे को आधार देने वाले विश्वास की रक्षा कर सकते हैं। साथ मिलकर, हम एक वित्तीय परितंत्र के निर्माण में सहयोग और नवोन्मेष जारी रखेंगे जो न केवल सुरक्षित और संरक्षित है बल्कि तेज, सुविधाजनक, सुलभ और किफायती भी है। आइए हम ऐसी वित्तीय प्रणाली बनाएं जो धन शोधन, आतंकवाद का वित्तपोषण और 'प्रसार वित्तपोषण' के प्रयासों को विफल करने के साथ-साथ वित्तीय समावेशन का समर्थन करे, नवोन्मेष को प्रोत्साहित करे और आर्थिक संवृद्धि को अवरोध रहित बनाए। अंत में, मैं उर्वर विचार-विमर्श की कामना करता हूं।

धन्यवाद।